# कृषि विविधीकरण: संभावनाएं एवं सीमाएं

कृष्णपाल एवं ऋचा खन्ना
आई. एफ. टी. एम. विश्वविद्यालय मुरादाबाद, 244102

यह बात सत्य है कि समय के साथ–साथ हमारी आवश्यकताएं एवं निर्भरता बदल जाती है। यदि हम कोरोना महामारी के समय की बात करें तो हमारे सामने दो मुख्य चुनौतियां मुंह बाहें खड़ी थी पहली चुनौती यह थी कि हम किस प्रकार से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखें और दूसरी चुनौती यह थी कि हम अपना जीविकोपार्जन कैसे करें।

**चित्र: कृषि विविधीकरण के घटक**

कोरोना महामारी के समय इन दोनों ही चुनौतियों से सामना करने में कृषि क्षेत्र ने संबल प्रदान किया। आपने महसूस भी किया होगा कि जब हमारे मानव श्रम का एक बड़ा भाग लॉक डाउन होने के कारण अपनी रोजी–रोटी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लौट रहा था तो वह कृषि क्षेत्र ही था जिसने उनको सहारा दिया। आपने देखा और सुना होगा कि विभिन्न संस्थाओं जैसे आयुष मंत्रालय द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर विभिन्न प्रकार के पादप निर्मित पेय पदार्थों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी थी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि जब यह मानव श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लौटकर कृषि क्षेत्र में अपनी जीविकापार्जन के लिए लगा तो कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड की गई।

वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार हम शहरी क्षेत्रों से पलायन मानव श्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में रुके रखें जिससे कि हमारे शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम रहे तथा कृषि क्षेत्र को भी उपयुक्त मानव श्रम मिलता रहे। इसमें दो राय नहीं है कि कृषि का विविधीकरण ही मात्र एक उपाय है जिसके द्वारा हम मानव श्रम को शहरी क्षेत्रों में जाने से रोक सकते हैं।

## विविधीकरण की परिभाषा

विविधीकरण में विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, सूअर, बकरी, भेड़ पालन, खरगोश पालन, आदि में संलग्न करने के लिए संदर्भित किया जाता है। विविधीकरण कृषि आय को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक रणनीति बन सकती है, जो फसल की खराबी के जोखिम को कम करती है और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करती है।

**फसल विविधीकरण**

पारंपरिक धान–गेहूं फसल प्रणाली की जगह फसल विविधीकरण को अपनाकर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इससे आमदनी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं।

सिंधु–गंगा के मैदानी इलाकों में संभावित विकल्प के रूप में मक्का–सरसों–मूंग एवं मक्का–गेहूं–मूंग फसल प्रणाली से उत्पादन की लागत में 15–25 प्रतिशत की कमी एवं 20–35 प्रतिशत कुल आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस प्रणाली से 65 से 70 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत भी कर सकते हैं। फसल विविधीकरण से कार्बन का संचय एवं मृदा की उर्वराशक्ति बनी रहती है। इससे फसल से संबंधित कीटों एवं रोगों के प्रभाव को नियोजित किया जा सकता है।

## संभावनाएं:

जीवन स्तर में बदलाव: आज विकसित देशों की तरह विकासशील देशों में भी लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। हमारे देश में जनसांख्यिकी का एक बड़ा वर्ग है जिसकी खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है और कोरोना महामारी के समय में वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी है, जिसकी वजह से आज वह अपने खानपान पर विशेष ध्यान दे रहा है। आज हम अपने भोजन में बहुत से स्रोतों जैसे खाद्यान् फसले, दलहन, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, फल सब्जी यहां तक की विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों से प्राप्त उत्पादों को सम्मिलित कर रहे हैं, ऐसे में कृषि विविधीकरण की पर्याप्त संभावनाएं हैं हमें इस अवसर का परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लाभ उठाना चाहिए।

## जनसांख्यिकी का बदलना:

विकासशील देशों में तेजी से शहरीकरण, खपत पैटर्न को प्रभावित करता है। इसके अलावा, किसानों की एक छोटी संख्या, कम से कम प्रतिशत के संदर्भ में, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती है। हालांकि इसका अर्थ

विविधीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च मांग को पूरा करने के लिए नई कृषि तकनीकों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

**निर्यात:**

वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में कृषि उपज उत्पाद के देशीय एवं अंतर्देशीय निर्यात की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उत्पाद निर्यात के लिए आवश्यक मांगों को पूरा करता हो। आज हम कृषि उपज उत्पादों में विविधीकरण लाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ–साथ अपने किसानों की दशा एवं दिशा में सुधार ला सकते हैं जिससे ना केवल हमारा देश वैश्विक स्तर पर सशक्त एवं समृद्ध होगा बलिक हमारे ग्रामीण परिवेश में भी खुशहाली आएगी।

**कृषि उत्पाद आधारित उद्योग धंधों का विविधीकरण:**

आज हम प्रायः देख रहे हैं कि कृषि उत्पाद आधारित नए–नए लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे विकसित किए जा रहे हैं, जबकि पहले के वर्षों में कृषि उत्पाद आधारित उद्योग धंधों में गिने चुने उद्योग धंधे ही थे जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि।

परंतु वर्तमान समय में नए–नए लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे जैसे मत्स्य पालन, सूकर पालन, कुकुट पालन, डेयरी उद्योग, खाद्य पदार्थों का परीक्षण, नर्सरी ना जाने कितने नए–नए उधम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे हैं जो एक प्रकार से कृषि विविधीकरण के घटक ही हैं।

**विपणन के अवसरों को बदलना:**

जिस तरह से किसान बाजारों से जुड़ सकते हैं, उसे नियंत्रित करने वाली सरकारी नीतियों में बदलाव से विविधीकरण की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, सभी लेन–देन को संभालने के लिए राज्य के "विनियमित बाजारों" के एकाधिकार को हटाने के लिए नीति में बदलाव ने किसानों के लिए नए उत्पादों के लिए खरीदारों के साथ सीधे अनुबंध स्थापित करना संभव बना दिया।

**प्रबंधन एवं रखरखाव:**

यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी उधमी के लिए यदि वह एक से अधिक कृषि पर आधारित उधम अपनाता है तो उसके लिए उन उधमों का प्रबंधन एवं रखरखाव कठिन होता है। यदि कोई भी उधमी या किसान कृषि विविधीकरण अपनाता है तो उसे पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उनका प्रबंधन किस प्रकार से करेगा।

**जानकारी एवं प्रशिक्षण का अभाव:**

प्राय देखने में यह आया है कि कभी–कभी हम उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण के अभाव में यदि कोई नया उधम अपनाते हैं तो हमें आर्थिक क्षति हो सकती है। अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो किसान अभी भी अपने परंपरागत कृषि उधमों को प्राथमिकता देते हैं, और नए–नए उधमों के बारे में जानकारी नगण्य होती हैं। परंतु सरकारी प्रोत्साहन की वजह से नए उधमों को अपना लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जानकारी उचित जानकारी न होने के कारण असफल हो जाते हैं।

**जोखिम न उठा पाने की क्षमता:**

अभी तक प्रायः देखने में आया है कि भारतीय किसान के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता नगण्य होती है, जिसकी वजह से वह कृषि विविधीकरण से दूर बने रहना चाहता है और अपनी परंपरागत रूप से मुख्य उसी उधम को अपनाता रहता है जिसे वह पहले से करता आ रहा हैं।

**पूंजी का अभाव:**

यह बात सत्य है कि यदि हम कोई भी नया उधम अपनाते हैं तो प्रारंभ में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु भारतीय किसान आर्थिक रूप से इतना सशक्त वह समृद्ध नहीं है कि वह नया उधम लगाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कर सकें। यद्यपि बहुत सी ऐसी सरकारी एवं और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो किसानों को उचित ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराती हैं लेकिन किसान इसको लेकर डरता है और उसके मन में अनिश्चितता बनी रहती है।

**विपणन में अनिश्चितता:**

कृषि विविधीकरण की राह में यह मुख्य अवरोध की तरह कार्य करता है। यदि कोई किसान या उधमी कोई नया उधम स्थापित भी कर लेता है और उसके उत्पाद के लिए उचित बाजार ने मिल पाने की दशा में वह हतोत्साहित होकर बैठ जाता है और भविष्य में नया उधम लगाने की कल्पना मात्र से भी सिहर जाता है साथ ही साथ इसको देख कर दूसरे किसान भी कृषि विविधीकरण को अपनाने से डरते हैं।

**निष्कर्ष :**

कृषि क्षेत्र भारत की 60 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है, इसलिए रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों का विकास जैसे, कृषि उद्योग, ई–मार्केटिंग, जैविक खेती, अग्रिम सिंचाई प्रणाली, विस्तार, कम लागत के इनपुट, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, सहायक बुनियादी ढांचे, आदि को इस क्षेत्र में अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारत ने साठ के दशक के बाद कृषि क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है क्योंकि इस अवधि में गेहूं और चावल का उत्पादन क्रमशः 10 और 4 गुना बढ़ा है। विविधीकरण में विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, सूअर, बकरी, भेड़ पालन, खरगोश पालन, आदि में संलग्न करने के लिए संदर्भित किया जाता है।

विविधीकरण कृषि आय को बढ़ा के लिए एक आवश्यक रणनीति बन सकती है, जो फसल की खराबी के जोखिम को कम करती है और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करती है। कृषि विविधीकरण गरीबी उन्मूलन और किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विविधीकरण देश को सामाजिक–आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

भारत कृषि क्षेत्र वर्तमान युग में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव से उत्पन्न आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना कर रहा है। स्थायी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए आने वाले वर्षों में कृषि विविधीकरण एक कुशल और प्रभावी प्रबंधन सिद्ध होगा।

इसलिए विदेशी प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भारतीय कृषि में विविधता आनी चाहिए और प्रत्येक किसान को अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लानी होगी। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार व किसानों को उपयुक्त कृषि विविधीकरण नीति का पालन करना होगा।